EDITORIAL

VRS 2.0 in BSNL

The BSNL management once again has rubbed the salt on the wound of the body of the suffering employees of BSNL by approving the proposal of VRS -2.0 with expectation of out go of about 19000 employees mixing both from executive and non-executive. The news of this VRS were floated in social media in the month of October 2024, and all the unions and associations functioning in BSNL jointly met to the CMD BSNL and submitted a memorandum opposing the proposal of VRS 2.0 in BSNL. The CMD BSNL in presence of all the General Secretaries of the unions and associations clearly denied and told that there is no proposal of such steps in the Company and he asked the representatives to motivate the employees to contribute better to enhance the market share of the Company and the representatives accepted the view of CMD and appealed to him for early implementation of 4G based mobile services to generate more revenue of the company.

On 4th October, 2024 in a meeting with NFTE representatives the Director (HR) also denied about the proposal of the VRS 2.0 in the company.

The employees representatives informed the workforce as per the view shared by the heads of the top management and the storm was stopped for the sometime. Again in the month of December, 2024 the news regarding VRS 2.0 started floating not only in social media but in print as well as electronic media also that the proposal of the VRS 2.0 is under move in BSNL and the entire work force came in curiosity regarding the factual position. The representatives of the unions/associations were in dilemma that how the management is moving forward with a policy of 2nd VRS without consulting with the stake holders of the Company. The top level officers of the management were also not ready to open their mouth, so. The situation became such awkward which was never seen in the Company. When the top officers of the management are not in a position to clarify the news of VRS 2.0 and the 2nd top level officers are not ready to open their mouth in this regard.

In this situation the representatives were not in the position to reply their members and share the factual position in respect of 2nd VRS.

Suddenly after approval of the proposal of VRS by the BSNL/MTNL management the news leaked and came to the knowledge of the representatives of union and association.

After approval of the proposal on 23-12-2024, the attention of the entire workforce of BSNL has been diverted from their work and responsibility to the discussion on VRS. The entire workforce came in unrest and the BSNL services started to be hampered badly. Now, the fact is before all of us that the BSNL management committee as well as the BSNL Board have approved the proposal of VRS -2.0 and it has been sent to the DOT for further decision.

It is also fact that all the unions and associations have opposed this steps of Govt/BSNL management and watching for the further steps of the DOT/Govt.

The Govt has not taken a lesson by implementation of three times VRS in MTNL, which was implemented to reduce the expenses on staff salaries etc, but ultimately the MTNL company is

sinked and now the company is at the verge of closure. It seems that the Govt wants to apply the same experiment for closure of the BSNL also.

The Govt did not taken lesson from the 1st VRS in BSNL also.

The Revenue as it was earning before VRS -19 became just half after the VRS and the salary of the employees were not even paid on time.

The Govt as well as BSNL management is taking the issue on the plea that the expenditure on staff is 38% of the revenue earned in the company. Due to their short sightedness they can not look and understand the exact reason of reduction of revenue. It is beyond the understanding of the management/Govt that the services based on 4G/5G Technology is the prime need and demand of the Telecom sector to provide a need based data services to the public but in the name of Swadeshi the BSNL pushed 12 years back in this area. It is the BSNL workers both executives and non-executives who are working with vision and dedicatedly contributing better to generate the revenue by several type of services of the BSNL.

The BSNL/DOT has requested the finance ministry a grant of Rs. 15000/ crore to implement the VRS -2.0 by which the salary bills of staff may reduced from 7500/- crore to 5000 crores. It is also much surprising that for reduction of 2500/- crore the management/Govt is going to send out 19000 of experienced employees (Executive and Non-executives) of the company and it is well known that to run the services the Govt/Management will outsource the services to some more Vendor/Contractor and further reduction of the revenue will come. The Govt will hand over the company to the any of the Corporate house through private partnership policy. Ultimately the way of the methodology applied by the Govt for revival of BSNL will go to the door of privatization only. **The stand of NFTE on VRS 2.0 is clear that we will strongly oppose the VRS 2.0 and motivate the workers not to opt for VRS because it is not only individual suicidal but also it will be a cheating with the people of the county who are the real owner of the BSNL.**

संपादकीय

बी.एस.एन.एल में बी.आर.एस.2.0

बी.एस.एन.एल प्रबंधन समिति एवं बी.एस.एन.एल बोर्ड ने बी.एस.एन.एल कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पुनः दुसरी बार अनुमोदित करके समस्त कर्मचारियों के शरीर पर उभरते घाव नमक रगड़ने का काम किया है।

बी.एस.एन.एल के लिए वी.आर.एस. की गुंज सोशल मीडिया ने अक्टूबर 2024 में ही सुनाई पड़ने लगी थी। इस वायरस समाचारों की पृष्टि के लिए सभी एक्जीक्यूटिव एवं नान–एक्जीक्यूटिव कर्मचारी संगठनों के महामंत्री सी.एम.डी बी.एस.एन.एल से मिले और एक संयुक्त ज्ञापन भी समर्पित किया। उस समय सी.एम.डी–बी.एस.एन.एल ने वी.आर.एस की बात को खारिज करते हुए कहा कि इस प्रकार की कोई मुद्दा विचारणीय नहीं है। आज सभी निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए कंपनी की मार्केट शेयर बढ़ाते हुए इसे 25 प्रतिशत करने की दिशा में आगे बढ़े। सभी प्रतिनिधियों ने माननीय सी.एम.डी को आश्वस्त किया कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रयास हो, कर्मचारीगण पूर्ण सहयोग के लिए हर वक्त तत्पर रहेंगे।

निदेशक (कार्मिक) ने भी 4 अक्टूबर को एन.एफ.टी.ई नेतृत्व के साथ एक औपचारिक बैठक के दरम्यान बी.आर.एस के प्रस्ताव से इनकार किया। संगठन नेताओं ने उच्चपदस्थ प्रबंधन के वार्ता पर पूर्ण विश्वास करते हुए संपूर्ण राष्ट्र में यह संवाद दिया कि वी.आर.एस नहीं आयेगी और सभी लोग निष्ठापूर्वक कार्य करें। इसके उपरान्त तूफान की गति से फैल रहे वी.आर.एस के समाचारों पर विराम लगा।

दिसंबर 2024 के पुनः वी.आर.एस के समाचार ना केवल सोशल मीडिया में अपितु समाचार पत्रों एवं चैनलों पर भी आये तथ्य एक कार किया पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर बी.एस.एन.एल कर्मचारियों के बीच विस्मय, सहित आक्रोश उबलने लगे चारों तरफ केवल वी.आर.एस की बातें होते रही। जिज्ञासावश फील्ड से बहुतायत संख्या में टेलीफोन काल सभी नेताओं के लिए आने लगे और स्थिति स्पष्ट नही होने के कारण संघ के नेता भी मुश्किल में थे। कोई अधिकारी अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था और कोई कुछ कहता भी तो उलट–पलट बातें कहकर अपना नाम नहीं आ जाये ऐसा व्यवहार करते। इस स्थिति को अराजक स्थिति ही कही जा सकती है। कंपनी के अस्तित्व में आने से लेकर अभी तक इस तरह की अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना नहीं पड़ा था। यह बात समय से परे थी कि अगर प्रबंधन वी.आर.एस चाहती है तो उन्हें श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों को सच्चाई बताने से कौन रोक रहा था या किस भय के कारण सब कुछ गुप्त रुप से संचालित हो रहा था। दिसंबर 2024 जब बी.एस.एन.एल एवं एम.टी.एन.एल प्रबंधन ने प्रबंधकीय समिति से वी.आर.एस के प्रस्ताव को पारित कर दिया तो यह समाचार गुप्त नहीं रह सका और जंगल में आग की तरह फैल गया। 23.12.2024 को प्रबंध समिति द्वारा बी.आर.एस के प्रस्ताव पारित हो जाने के उपरान्त समस्त कर्मचारियों का ध्यान सभी जिम्मेवारियों को छोड़कर वी.आर.एस के मामले के ओर आकृष्ट हो गया। बी.एस.एन.एल की सेवाओं पर इसका प्रतिकुल प्रभाव हुआ इसलिए कि यह समाचार के सभी कर्मियों को हतप्रत करने के साथ आक्रोशित भी कर दिया और कर्मचारी अपने संगठन के प्रतिनिधियों से सवाल करने लगे कि निगम बनाते समय तत्कालीन सरकार ने नौकरी की सुरक्षा की बात की थी उसका क्या हुआ? सरकार ने कंपनी को आर्थिक रुप से जीवंत रखने की बातें की थी उसका क्या हुआ? सरकारी पेंशन की गारंटी दी गई थी उसका क्या हुआ? जबकि आज लाखों पेंशन प्राप्त कर्मचारी पेंशन पुनरीक्षण के लिए दर–दर की ठोकरे खा रहे हैं।

यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार येन–केन प्रकारेण न कर्मचारियों को बाहर करके कंपनी के समस्त संचालन निजी ठेकेदारों के हाथ में देना चाहती है। यह भी स्पष्ट है कि बी.एस.एन.एल में संचालित सभी यूनियन एवं एसोसिऐशन ने वी.आर.एस–2 का विरोध किया है, तथा बी.एस.एन.एल प्रबंधन समिति एवं बोर्ड द्वारा वी.आर.एस प्रस्ताव के मंजूरी देकर उसे दूरसंचार विभाग में आगे की कार्यवाही के लिए भेज देने के उपरान्त सरकार एवं बी.एस.एन.एल प्रबंधन के अगले कदम की ओर देख रहे हैं।

सरकार एवं संबंधित अधिकारियों ने एम.टी.एन.एल में किये गये तीन बी.आर.एस के बावजूद उस कंपनी की अधिक सेहत सुधारने के बजाय बिगड़ती गई और कंपनी डूबने के कगार पर ही नहीं पहुंची है, अपितु डूब चुकी है और सरकार ने एम.टी.एन.एल की सेवाओं को बी.एस.एन.एल को सुपुर्द करने का निर्णय लिया है।

यह कैसी विडम्बना है कि एक तरफ सरकार एम.टी.एन.एल की सेवाओं को बी.एस.एन.एल को सुपुर्द करने जा रही है ओर दूसरी ओर बी.एस.एन.एल के कर्मचारियों को भी बी.आर.एस के द्वारा बाहर कर देना चाहती है तो सेवाओं का रख–रखाव किसके द्वारा कराई जायेगी। इन परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार की रुचि इन लोक उपक्रमों को पूर्णतः बंद कर देने में है अथवा इसे जर्जर स्थिति में पहुंचाने के बाद निजी हाथों में दे देना चाहती है।

बी.एस.एन.एल के प्रथम वी.आर.एस जो 31 जनवरी 2020 को लागू किया गया। इस बी.आर.एस के द्वारा सरकार की सोच थी कि 35000 से 40000 कर्मचारी कंपनी से बाहर जायेंगे परंतु विभिन्न कारणों से प्रताड़ित कर्मचारियों ने 80 हजार के तदाद में बाहर चले गये। यह भी विचारणीय है कि इस वी.आर.एस के उपरांत बी.एस.एन.एल की वार्षिक राजस्व लगभग 50% कम हो गई और जो कर्मचारी सेवा में बचे उन्हें समय पर वेतन मिलना भी दुर्लभ हो गया। यह उच्च पदस्थ प्रबंधन की अदूरदर्शिता ही है कि वे कर्मचारियों पर होने वाले खर्च को ही कंपनी के अधिक गिरावट का कारण मानते हैं। कंपनी की राजस्व बढ़ाने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। प्रबंधन कहती है कि बी.एस.एन.एल के कुल राजस्व का 38% कर्मचारियों पर खर्च होता है। अगर वी.आर.एस–3 देने के बाद कर्मचारियों पर होने वाले कुल 7500 करोड़ रुपये की जगह केवल 5000 करोड़ रुपये ही खर्च होगा। अगर इस प्रकार 2500 करोड़ रुपये की बचत होगी।

यह कैसी विडम्बना है कि सरकार/प्रबंधन 2500 करोड़ रुपयों के बचत के लिए अपने अनुभवी कर्मचारियों को 19000/20000 लोगों को बाहर करना चाहती है। यह कैसी स्थिति है जैसे परिवार की खर्च घटाने के लिए परिवार की आय बढ़ाने के बजाय परिवार के व्यक्तियों की संख्या कम कर दी जाये।

यह स्पष्ट है कि बी.एस.एन.एल में बाधित राजस्व की प्राप्ति नहीं होने के पीछे बी.एस.एन.एल को 4 जी/5 जी आधारित सेवाओं से वंचित रखना है। ज्ञातव्य है कि निजी कंपनियों 2012 से ही 3 जी आधारित सेवा विदेशी उपकरणों के माध्यम से दे रही है और सरकार ने बी.एस.एन.एल को स्वदेशी उपकरण के द्वारा ही 4जी/5जी सेवा देने की शर्त रखकर बी.एस.एन.एल को 12 साल पीछे धकेल दिया गया है। आज भी त्वरित डाटा के साथ बी.एस.एन.एल सेवा नहीं दे सकती है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि राजस्व की कमी के कारणों में सरकार की नीतियों और प्रबंधन की अदूरदर्शिता ही कारण बनती है।

बी.एस.एन.एल के एक्जीक्यूटिव एवं नान–एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों के कंपनी के प्रति निष्ठा सके उनके अथक कार्य सम्पादन का ही फल है कि कंपनी 3 जी आधारित सेवा एवं अन्य सेवाओं से वर्तमान राजस्व की प्राप्ति करा रहें हैं।

खबर मिली है कि बी.एस.एन.एल प्रबंधन ने वी.आर.एस–2 के लागू करने के लिए सरकार से 15000 करोड़ रुपये की मांग की है।

इन परिस्थितियों से स्पष्ट हो रहा है कि वी.आर.एस–2 के संचालन हेतु निजी ठेकेदारो को सुपुर्द किया जाएगा जैसा कि प्रथम बी.आर.एस के बाद किया गया, और उनका प्रतिफल यह हुआ कि बी.एस.एन.एल की सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट आते जा रही है।

सरकार द्वारा बी.एस.एन.एल के उत्थान के लिए उठाये गये तरीके कंपनी को निजी निगमित घरानों के द्वारा तक पहुंचा देगी ऐसी चर्चा अब आम हो चली है।

एन.एफ.टी.ई का वी.आर.एस–2 के निर्णय में यह स्पष्ट निर्णय है कि हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और कर्मचारियों को जागृत करेंगे कि वे वी.आर.एस के भुल–भुलैया में नहीं पड़े यह किसी भी कर्मचारी के लिए न केवल आत्मघाती होगा अपितु यह देश की जनता के प्रति धोखा होगा जो इस कंपनी के वास्तविक मालिक है।